



बैंकगि क्षेत्र: अवसर और चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 29/12/2023 को 'हद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित ["Banks are fine, but there are risks"](#) लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि भले ही बैंक सुदृढ़ स्थिति में नज़र आते हैं लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति, अत्यधिक गर्म शेयर बाज़ार और अंतर-संबंधित ऋण चिंता का वषिय है।

प्रलम्ब के लिये:

[बैंकगि क्षेत्र, भारतीय रज़िर्व बैंक, गैर-नषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ, त्वरति सुधारात्मक कार्रवाइयाँ।](#)

मेन्स के लिये:

[बैंकगि क्षेत्र में चुनौतियाँ।](#)

लगभग एक दशक तक 'बैड लोन' (bad loan) की बढ़ती चुनौतियों से जूझने के बाद हाल के समय में भारत की बैंकगि प्रणाली में उल्लेखनीय पुनरुत्थान नज़र आया है। नीतनिर्माताओं के ठोस प्रयासों और बैंकों द्वारा उठाये गए सक्रिय कदमों की बदौलत बैंकगि क्षेत्र वर्तमान में अधिक सुरक्षित स्थिति में है।

हालाँकि ऐतिहासिक पैटर्न को ध्यान में रखें तो भारतीय बैंकों के लिये सकारात्मक प्रक्षेपवक्र मौद्रिक नीतियों और भू-राजनीतिक जोखिमों जैसी बाहरी अनिश्चितताओं के प्रभाव के प्रति अभी भी संवेदनशील बना हुआ है।

समय के साथ भारतीय बैंकों का विकास कसि प्रकार हुआ?

- पहली पीढ़ी की बैंकगि (आरंभ से वर्ष 1947 तक):
 - स्वतंत्रता से पहले की अवधि में [सवदेशी आंदोलन](#) के कारण कई छोटे एवं स्थानीय बैंकों की स्थापना हुई, जिनमें से अधिकांश को मुख्य रूप से आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर-संबंध उधारी और व्यापार एवं बैंकगि गतिविधियों के एकीकरण के कारण वफिलता का सामना करना पड़ा।
- दूसरी पीढ़ी की बैंकगि (1947-1967):
 - भारतीय बैंकों ने संसाधनों के समेकन को सक्रिय किया, जो सीमति संख्या में व्यावसायिक परिवारों या समूहों के लिये खुदरा जमा के माध्यम से जुटाए गए और जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह की अनदेखी हुई।
- तीसरी पीढ़ी की बैंकगि (1967-1991):
 - सरकार ने [दो चरणों \(वर्ष 1969 और वर्ष 1980\) में 20 प्रमुख नज़ि बैंकों के राष्ट्रियकरण](#) और वर्ष 1972 में [प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण](#) की शुरुआत कर उद्योग एवं बैंकों के बीच के संबंध को सफलतापूर्वक भंग कर दिया।
 - इन उपायों से 'क्लास बैंकगि' से 'मास बैंकगि' की ओर संक्रमण की राह खुली और ग्रामीण भारत में शाखा नेटवर्क के व्यापक वस्तितार, सार्वजनिक जमा की पर्याप्त गतिशीलता और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।
- चौथी पीढ़ी की बैंकगि (वर्ष 1991-2014):
 - इस अवधि के दौरान प्रतसिपर्द्धा शुरु करने, उत्पादकता में सुधार लाने और दक्षता बढ़ाने के लिये नज़ि एवं वदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी करने सहित कई महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किये गए।
 - इन परिवर्तनों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, वविकपूर्ण मानदंडों को लागू करना, कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ परिचालनात्मक लचीलेपन की पेशकश करना, सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यासों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना और [बेसल मानदंडों \(Basel norms\)](#) के अनुसार पूंजी आधार को सुदृढ़ करना शामिल रहा।
- वर्तमान मॉडल:
 - वर्ष 2014 के बाद से बैंकगि क्षेत्र ने [JAM टरनिटि \(जन-धन, आधार और मोबाइल\)](#) को अपनाया है और वित्तीय समावेशन की खोज में अंतमि-मिल कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिये [भुगतान बैंकों \(Payments Banks\)](#) एवं [लघु वतित बैंकों \(SFB\)](#) को लाइसेंस प्रदान किया है।

भारतीय बैंकगि व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है?

- पृष्ठभूमि:

- नकित अतीत में भारतीय ऋणदाताओं को 'बैड लोन' की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण तनावग्रस्त परसिंपत्तियों (stressed assets) में वृद्धि हुई थी। इससे सरकारी स्वामित्व वाले बैंक वशेष रूप से प्रभावित हुए, जिनका सकल NPAs 14.6% तक पहुँच गया था।
- इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये सरकार और भारतीय रज़िर्व बैंक ने 4R रणनीति लागू की: NPAs को पारदर्शी रूप से चिह्नित करना (Recognize NPAs transparently), समाधान एवं वसूली (Resolution and recovery), सार्वजनिक बैंकों का पुनर्पूँजीकरण (Recapitalization of PSBs) और वित्तीय पारस्थितिकी तंत्र में सुधार (Reforms in the financial ecosystem)।
- लगभग एक दशक तक सरकार की कमज़ोर हालत और बैड लोन के मुद्दों से जूझने के बाद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वर्ष 2023 में एक उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया है।
- **लाभप्रदता और परसिंपत्तगुणवत्ता में सुधार:**
 - वित्त वर्ष 2013 में भारत में बैंकों का सकल NPA अनुपात गरिकर 4.41% हो गया जो मार्च 2015 के बाद से नमिनतम स्तर है। संचयी रूप से, PSBs ने लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर लिया।
 - RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार पूँजी-जोखमि-भारति संपत्ति अनुपात (CRAR) 16.8% के सुदृढ़ स्तर पर है, जो अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों के लिये एक मज़बूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है।
 - यह भारतीय बैंकों के अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य को रेखांकित करता है, जो संभावित जोखमिों को अवशोषित करने और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने की उनकी क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रतबिबिति करता है।
- **नीति सुधार और वित्तीय अनुशासन:**
 - पछिले आठ वर्षों में शुरू किये गए विभिन्न सुधार उपाय ऋण अनुशासन, उत्तरदायी उधारी या ऋणदेयता, बेहतर प्रशासन और प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आपसी वलिय भी NPA को कम करने में सहायक रहा।
- **मज़बूत वित्तीय संकेतक:**
 - बैंक मज़बूत तरलता स्तर प्रदर्शति कर रहे हैं, जसि ऋण देने के लिये उपलब्ध नधियों के आधार पर मापा जाता है। RBI द्वारा हाल में 'withdrawal of accommodation' का मौद्रिक रुख अपनाये जाने के बावजूद भारतीय बैंकों ने न्यूनतम आवश्यकता से कम से कम 20% अधिक तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखा है।
 - इसके अतरिकित, SBI, PNB और यूनियन बैंक सहित विभिन्न प्रमुख बैंकों ने 72% से कम क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात (Credit-Deposit ratios) के साथ 'higher for longer' ऋणदेयता की क्षमता प्रदर्शति की है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिये आगे कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं?

- **अवसंरचना और पूँजी नविश जोखमि:**
 - आगामी अवसंरचना और पूँजी नविश के लिये बैंक ऋण, वशेष रूप से राज्य सरकार के नकियों से जुड़े ऋण, राज्य के वित्त में खचाव के कारण 'डिफॉल्ट' का जोखमि पैदा करते हैं।
 - बैंकों को सलाह दी जाती है कवि अलग-अलग राज्यों के राजकोषीय/वित्तीय आकलन के आधार पर आंतरिकि एक्सपोजर सीमाएँ (internal exposure limits) नरिधारति करें।
- **शेयर बाज़ार और खुदरा एक्सपोजर जोखमि:**
 - तेज़ी से बदलता शेयर बाज़ार, जो धन सृजन का भ्रम पैदा करता है, खुदरा एक्सपोजर (retail exposures) के लिये जोखमि प्रस्तुत करता है। सभी क्षेत्रों में बढ़े हुए 'डीमैट' खाते और उच्च PE अनुपात इस जोखमि के संकेतक हैं।
 - इस उभरते जोखमि से नपिटने के लिये खुदरा पोर्टफोलियो पर एकीकृत पर्यवेक्षण और कठोर तनाव परीक्षणों (stress tests) की अनुशंसा की जाती है।
- **परस्पर-संबद्ध ऋण और शासन संबंधी चुनौतियाँ:**
 - परस्पर-संबद्ध ऋण (Interconnected Lending) और ढीले शासन मानदंडों के कारण डिफॉल्ट के संक्रामक हो जाने की संभावना एक प्रमुख चुनौती है।
 - केंद्रति जोखमि नगिरानी आवश्यक है, इस बात पर बल देते हुए कविनियमन सुशासन का स्थान नहीं ले सकता।
- **पुनःवैश्वीकृत वशिव में SMEs की चुनौतियाँ:**
 - दुनिया का पुनःवैश्वीकरण (re-globalization) और भू-राजनीतिक बदलाव लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को वशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के परदृश्य में चुनौती दे सकते हैं।
 - नकदी प्रवाह में संभावित व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को SMEs के लिये संभावित जोखमिों का सावधानीपूर्वक आकलन करने और इस दशि में तैयारी करने की आवश्यकता है।
- **देनदारियों का बदलता परदृश्य:**
 - डिजिटलीकरण और उभरती उपभोग प्रवृत्तियों के साथ देनदारियों (liabilities) का चरतिर बदल रहा है, जसिका असर खुदरा जमा पर पड़ रहा है। उच्च क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात रखने वाले बैंकों को तरलता कवरेज में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
 - भारतीय बचत में संरचनात्मक बदलाव के लिये बैंकों की ओर से सतर्कता एवं वविक की आवश्यकता है, जहाँ अनुकूल परस्थितियों के बीच सावधानीपूर्वक नगिरानी आवश्यक है।

आगे बढ़ते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कसि प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- **बड़े बैंकों का नरिमाण:**
 - नरसहिम समति रिपोर्ट (1991) ने भारत के लिये वदिशी बैंकों के अलावा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उपस्थति रखने वाले तीन-चार प्रमुख वाणज्यिक बैंकों के होने के महत्त्व को रेखांकित किया।

- दूसरे स्तर में अर्थव्यवस्था में व्यापक उपस्थिति वाले वशिष्ट संस्थानों सहित कई मध्यम आकार के बैंक शामिल हो सकते हैं।
- इन सुझावों के अनुरूप, सरकार ने पहले ही कुछ PSBs को समेकित कर दिया है और **स्वकिसास वित्त संस्थान (DFI) एवं 'बैड बैंक' (Bad Bank)** जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिये उपाय किये हैं।
- **विविधता बैंकों के लिये आवश्यकताएँ:**
 - जबकि सार्वभौमिक बैंकिंग दृष्टिकोण को आमतौर पर पसंद किया गया है, विविध ग्राहकों और उधारकर्ताओं की वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अलग-अलग बैंकिंग संस्थाओं की मांग मौजूद है।
 - ये वशिष्ट बैंक खुदरा, कृषि और MSMEs जैसे वशिष्ट क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच की सुविधा प्रदान करेंगे।
 - इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित DFIs या वशिष्ट बैंकों (niche banks) को वशिष्ट संस्थाओं के रूप में स्थापित करने से उन्हें निम्न लागत वाली सार्वजनिक जमा तक पहुँच मिलेगी और बेहतर परसिंपत्त-देयता प्रबंधन संभव होगा।
- **ब्लॉकचेन बैंकिंग:**
 - इसकी मदद से उन्नत जोखिम प्रबंधन हासिल किया जा सकता है और नियो-बैंक (neo-banks) के पास डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और महत्वाकांक्षी एवं उभरते भारत की बढ़ती वृद्धि का समर्थन करने के लिये इस तकनीक का उपयोग करने का अवसर है।
 - भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में **ब्लॉकचेन** जैसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन में विकल्पपूर्ण पर्यवेक्षण को सुगम बनाने और बैंकों पर नगिरानी एवं नयितरण को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की क्षमता है।
- **नैतिक खतरे को संबोधित करना:**
 - अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विफल होने की घटनाएँ कम होती रही हैं, मुख्य रूप से इनमें नहिती संप्रभु गारंटी के कारण, जिससे आम लोगों में वृहत भरोसा पैदा होता है। लेकिन PSBs के नज्जिकरण की जारी प्रकिया इस आशवासन को चुनौती देती है।
 - बैंकिंग सुधारों की आगामी लहर में व्यक्तिगत जमा बीमा में वृद्धि और **कृशल व्यवस्थिति समाधान तंत्र की आवश्यकता** पर बल दिया जाना चाहिये। इसका उद्देश्य नैतिक खतरे एवं प्रणालीगत जोखिमों को कम करना और सार्वजनिक खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करना होना चाहिये।
- **ESG एकीकरण:**
 - वशिष्ट बैंकों के लिये एक प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना और **ESG (पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन)** ढाँचे को अपनाना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य दीर्घावधि में हितधारकों के लिये मूल्य को संवृद्ध करना है।
- **बैंकिंग संस्थानों को उन्नत बनाना:**
 - भेद्यताओं को दूर करने के लिये, सरकार को वनियामक उपायों को परष्कृत करना चाहिये, बैंकों को विविध ऋण पोर्टफोलियो विकसित कर सकने में सक्षम बनाना चाहिये, वशिष्ट क्षेत्रों के लिये नियामकों की स्थापना करनी चाहिये और जानबूझकर किये गए डिफॉल्ट से प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये अधिक अधिकार प्रदान करना चाहिये।
- **कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार विकास को सुगम बनाना:**
 - एक गतिशील वास्तविक अर्थव्यवस्था में एक उत्तरदायी बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिये **कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार** के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि बैंक-केंद्रित आर्थिक मॉडल से परे आगे बढ़ा जा सके।
- **जोखिम प्रबंधन मॉडल को उन्नत बनाना:**
 - राज्य सरकार के नकियाँ और अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिये राज्य वशिष्ट के अनुरूप **आंतरिक जोखिम मॉडल (बैंक एक्सपोज़र जोखिम सूचकांक के समान)** का विकास एवं कार्यान्वयन करें।
- **देनदारियों में परिवर्तन को संबोधित करना:**
 - **डिजिटलीकरण** और उभरते उपभोग रुझानों से प्रभावित देनदारियों की बदलती प्रकृति को चिह्नित करें। खुदरा जमा में बदलाव के अनुकूल रणनीति विकसित करें (वशिष्ट रूप से टयिर 1 और 2 केंद्रों में)।

नष्किकरष:

बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान सफलता का भले ही हम जश्न मनाएँ, लेकिन जिस समय में हम रह रहे हैं उसकी जटिलताओं एवं अनश्चितताओं से नपिटने के लिये सक्रिय एवं सतर्क रुख अपनाना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: नकिट अतीत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ प्रदर्शन के बावजूद कुछ जोखिम कारक संभावित चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। वसितार से चर्चा कीजिये और उचित उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न: 'बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं?

1. RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है।
2. BBB, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिये संसुतुत किरता है।
3. BBB, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्यानीतियों और पूँजी-वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

??????:

Q. बैंक खाते से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिये प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिये इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि के लिये उचित तर्क दीजिये। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/banking-sector-opportunities-and-challenges>

